एम. जयापॉल से पहले जे.

पंजाब वेक बोर्ड, चंडीगढ़-याचिकाकर्ता

बनाम

गुरदेव राज-प्रतिवादी

2012 की सीआर संख्या 5599

24 सितंबर 2012

पंजाब वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1955-एस.6 और 7-पंजाब वक्फ बोर्ड ने कब्जे और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें स्वामित्व का दावा किया गया और प्रतिवादी ने अनधिकृत कब्जे में होने का दावा किया, वक्फ ट्रिब्यूनल ने रखरखाव पर मुकदमा खारिज कर दिया - दायर संशोधन भी खारिज कर दिया - आयोजित - स्वामित्व वक्फ बोर्ड ने लिखित में स्वीकार किया - वक्फ ट्रिब्यूनल केवल यह तय कर सकता है कि वक्फ की सूची में उल्लिखित संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं - ट्रिब्यूनल के पास पक्षों के बीच विवाद का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और यह केवल सिविल कोर्ट है जिसका अधिकार क्षेत्र है सूट का मनोरंजन करने के लिए.

माना गया कि वक्फ अधिनियम की धारा 6(1) और 7(1) के तहत, ट्रिब्यूनल के पास यह सवाल तय करने का अधिकार है कि वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट संपत्ति

वक्फ संपत्ति है या नहीं। ट्रिब्यूनल यह भी तय करेगा कि ऐसी सूची में निर्दिष्ट वक्फ शिया वक्फ है या सनी वक्फ। ऐसे विवाद के संबंध में न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(पहरा न0 9)

इसके अलावा, यह माना गया कि वक्फ अधिनियम की धारा 85 के तहत सिविल न्यायालयों पर लगाई गई रोक वक्फ, वक्फ संपत्ति या अन्य मामले से संबंधित अन्य मामलों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक पाई गई है, जो अधिनियम के तहत निर्धारित किए जाने के लिए आवश्यक है। न्यायाधिकरण. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ''वक्फ, वक्फ संपत्ति से संबंधित अन्य मामले'' को वक् ख्अधिनियम, के विभिन्न प्रावधानों में विशेष रूप से संदर्भित किया गया है। मेरे विचार में, मुकदमे का दायरा अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत भी नहीं आता है जो वाकलैंड वाकल संपत्ति से संबंधित मामलों से संबंधित है।

(पहरा न0 10)

इसके अलावा, यह माना गया कि ऐसे मामले में भी जहां मुकदमा वक्फ बोर्ड की संपत्ति से किरायेदार को बेदखल करने के लिए नहीं है, कब्जे की वसूली के लिए दायर किया गया मुकदमा जहां वक्फ बोर्ड के स्वामित्व को स्वीकार किया गया था, ट्रिब्यूनल के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है पार्टियों के बीच विवाद का फैसला करने के लिए केवल सिविल न्यायालय को ही मुकदमे पर विचार करने का अधिकार है।

(पहरा न0 11)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील नीलोफर आबिदा परवीन।

(1) वादी-पंजाब वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ द्वारा कब्जे की डिलीवरी के साथ-साथ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर किया गया मुकदमा रखरखाव योग्य नहीं.

(2) वादी-पंजाब वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ द्वारा मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह मुकदमे की जमीन का मालिक था, जिसे वर्ष 1986-87 तक जीवन मल को पट्टे पर दिया गया था। जीवन मल की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी गुरदेव राज वादी-बोर्ड के तहत पट्टेदार नहीं बने, लेकिन उन्होंने मुकदमे की संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है। इसलिए, वादी-बोर्ड द्वारा कब्जे की डिलीवरी और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।

(3) प्रतिवादी ने इस आधार पर मुकदमे का विरोध किया कि मुकदमा स्वयं चलने योग्य नहीं था। यह भी तर्क दिया गया है कि जीवन मल नाम के प्रतिवादी के पिता ने मुकदमे की जमीन 99 साल के लिए पट्टे पर ली थी। 1994-95 में जीवन मल की मृत्यु पर, प्रतिवादी को मृतक जीवन मल का उत्तराधिकारी होने के नाते उसकी संपत्ति विरासत में मिली।

(4) ट्रिब्यूनल ने मुकदमे की स्थिरता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति ली और पाया कि, एलआरएस के माध्यम से रमेश गोबिंदराम (मृत) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में। बनाम सुगरा हुमांयूं मिर्जा वक्फ (1), कि वक्फ संपत्ति के कब्जे में किरायेदार को बेदखल करने का मुकदमा, जब वक्फ बोर्ड के स्वामित्व को स्वीकार किया गया था, ट्रिब्यूनल द्वारा मुकदमे को खारिज करने से पहले झूठ नहीं होगा क्योंकि यह मुकदमा कायम रखने योग्य नहीं था।

(5) पुनरीक्षण याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने रमेश गोबिंदराम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उपरोक्त निर्णय को ट्रिब्यूनल द्वारा गलत तरीके से पढ़ा गया है, क्योंकि उक्त निर्णय एक में लागू होगा मामला जहां वाक बोर्ड की संपत्ति से किरायेदार को बेदखल करने के लिए मुकदमा दायर किया गया है। ट्रिब्यूनल यह ध्यान देने में विफल रहा कि मुकदमा अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ दायर किया गया है, न कि वक्फ बोर्ड के किरायेदार के खिलाफ। इसलिए, उनका तर्क है कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश रद्द किया जाना चाहिए।

(6) मुझे लगता है कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा की गई दलील में कोई दम नहीं है। यह स्वीकृत स्थिति है कि वादीध्वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली वाद संपत्ति प्रतिवादी के पिता जीवन मल को पट्टे पर दी गई थी। जीवन मल के निधन के बाद, प्रतिवादी कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। प्रतिवादी ने स्पष्ट शब्दों में लिखित बयान में स्वीकार किया कि वक्फ बोर्ड वाद संपत्ति का मालिक है। ऐसी परिस्थितियों में, विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति के स्वामित्व को वास्तव में स्वीकार करने वाले व्यक्ति से कब्जा वापस पाने का मुकदमा 'ट्रिब्यूनल' के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 6 और 7 का संदर्भ लेना प्रासंगिक है। वक्फ अधिनियम की धारा 6(1) इस प्रकार हैः-

"6. वक्फ के संबंध में विवाद।-(1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट एक विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं या क्या ऐसी सूची में निर्दिष्ट वक्फ सुन्नी वक्फ का शिया वक्फ है, तो बोर्ड या वक्स के मुतवल्ली या उसमें रुचि

रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रश्न के निर्णय के लिए ट्रिब्यूनल में मुकदमा दायर कर सकता है और ऐसे मामले के संबंध में ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगाः

बशर्ते कि वक्फ की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसे किसी भी मुकदमे पर विचार नहीं किया जाएगा।" धारा 7(1) इस प्रकार हैः -

"7. संबंधित विवादों का निर्धारण करने के लिए न्यायाधिकरण की शक्ति

वक्फ.-(1) यदि. इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, कोई भी

प्रश्न उठता है कि क्या किसी विशेष संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है

वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, या

क्या ऐसी सूची में निर्दिष्ट वक्फ शिया वक्फ है या नहीं

सुन्नी वक्फ, वक्फ का बोर्ड या मुतवल्ली, या कोई उसमें रुचि रखने वाला व्यक्ति, ऐसी संपत्ति के संबंध में अधिकार क्षेत्र रखने वाले ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकता है, प्रश्न के निर्णय के लिए और उस पर ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगाः"

(8) धारा 6(1) में पाई गई वही विषय वस्तु वक्फएक्ट की धारा 7(1) में निपटाई गई है, अंतर यह है कि धारा 7(1) अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद उत्पन्न होने वाले विवादों को संदर्भित करती है।

(9) वक्फ अधिनियम की धारा 6(1) और 7(1) के तहत, ट्रिब्यूनल के पास इस सवाल का फैसला करने का अधिकार है कि वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। ट्रिब्यूनल यह भी तय करेगा कि ऐसी सूची में निर्दिष्ट वक्फ शिया वक्फ है या सनी वक्फ। ऐसे विवाद के संबंध में न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(10) वक्फ अधिनियम की धारा 85 के तहत सिविल न्यायालयों पर लगाई गई रोक वक्फ, वक्फ संपत्ति या अन्य मामलों से संबंधित अन्य मामलों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक पाई गई है, जो न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अधिनियम के तहत आवश्यक हैं। . यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वक्फ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में "वक्फ, वक्फ संपत्ति से संबंधित अन्य मामलों" को विशेष रूप से संदर्भित किया गया है। मेरे विचार में, मुकदमे का दायरा अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत भी नहीं आता है जो वक्फ और वक्फ संपत्ति से संबंधित मामलों से संबंधित है।

(11) यह सच है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रमेश गोबिंदराम के मामले में दिया गया उपरोक्त निर्णय वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष किरायेदारों को बेदखल करने के लिए दायर एक मुकदमे से संबंधित है, लेकिन उपरोक्त निर्णय में निर्धारित अनुपात इस मामले के तथ्यों पर लागू होगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल के समक्ष रखा गया वर्तमान मुकदमा मुकदमे की संपत्ति के रूप में वक्फ के स्वामित्व के किसी भी विवाद से संबंधित नहीं था। यहां तक कि ऐसे मामले में जहां मुकदमा वक्फ बोर्ड की संपत्ति से किरायेदार को बेदखल करने के लिए नहीं है, कब्जे की वसूली के लिए दायर किया गया मुकदमा जहां वक्फ बोर्ड के स्वामित्व को स्वीकार किया गया था, ट्रिब्यूनल के पास विवाद का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है पार्टियों के बीच और यह केवल सिविल कोर्ट है जिसके पास मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

(12) उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे लगता है कि ट्रिब्यूनल ने मुकदमे को खारिज कर दिया है क्योंकि यह चलने योग्य नहीं है। मुझे पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और इसलिए, पुनरीक्षण खारिज किया जाता है। लागत का कोई आदेश नहीं है.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु

न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा